TCI
LEADERS IN LOGISTICS

Transport Corporation of India Limited

Insurance Report Launch
Print Coverage

MOVING INDIA'S
GROWTH STORY.

Headline: 'No mandating of cover for goods in transit; it's insurers' business: Gadkari'

Publication: The Hindu Business Line

Edition: National

Link: https://www.thehindubusinessline.com/news/no-mandating-of-cover-for-goods-in-transit-its-insurers-business-gadkari/article23577094.ece

Ad Value: 80,000

No mandating of cover for goods in transit; it's insurers' business: Gadkari

OUR BUREAU
New Delhi, April 17

The Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, has said that details of insurance will have to be decided between the consumer and the transporter.

It is the job of insurer to convince the transporter, he said.

While launching a report of the Transport Corporation of India and Insurance Institute of India, here on Tuesday, he said that the report recommends that logistics service providers may appeal to the Ministry to make insurance mandatory for all transported goods – at least those moved by through third party logistics service providers.

As logistics has become integrated with supply chain, services have become more complex and setting limits on liability has become difficult, the study said citing UNESCAP.

Freight charges

Freight charged by logistics service providers is not sufficient to meet the risk exposure of transportation and warehousing losses even though the losses are infrequent, the study found.

Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport and Highways

Big logistics players can think of creating protection and indemnity clubs to take care of those risks and claims that are not covered under insurance policies, recommended the study.

Carriers legal policies need to be rejigged by insurers after understanding the present day realities of the logistics and warehousing industry, it added.

There are several insurance requirements of the logistics industry which are not designed by the insurers, said the study.

Headline: Delhi-Mumbai expressway work to start soon
Publication: Rashtriya Sahara
Edition: National
Ad Value: 1,86,390

जल्द शुरू होगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दिल्ली और मुंबई के बीच बनने वाले नए एक्सप्रेस-वे का काम एक महीने में शुरू हो जाएगा जिससे राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच की दूरी तकरीबन 135 किलोमीटर कम हो जाएगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में बताया कि नए एक्सप्रेस-वे पर बड़ौदा-मुंबई खंड के पांच में से चार पैकेज के लिए ठेके आवंटित किए जा चुके हैं। पांचवें पैकेज का ठेका एक महीने में आवंटित हो जाएगा। इसके बाद इस खंड पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली-बड़ौदा खंड पर भी इसी साल काम शुरू होने की उम्मीद है।

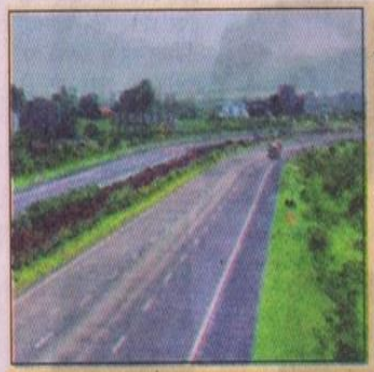

- नए एक्सप्रेस वे से 135 किलोमीटर कम होगी दोनों महानगरों की दूरी
- सफर का समय भी 40% घटकर 11 घंटे के करीब रहने की उम्मीद
- रफ्तार बनाए रखने के लिए एक्सप्रेस वे पर नहीं बनाया जाएगा चेक पोस्ट
- एक्सप्रेस वे के बड़ौदा-मुंबई खंड पर आवंटित किए गए चार ठेके
- हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरेगा एक्सप्रेस वे

श्री गडकरी ने भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) और भारतीय परिवहन निगम (टीसीआई) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एक रिपोर्ट की लांचिंग के मौके पर कहा कि दिल्ली-मुंबई के मौजूदा सड़क मार्ग से एक्सप्रेस-वे का रास्ता अलग और छोटा होगा। नया एक्सप्रेस बनने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी करीब 135 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर घटकर 11 घंटे का रह जाएगा। इस प्रकार समय में 40 प्रतिशत की बचत होगी। इस पूरे एक्सप्रेस-वे पर कोई चेकपोस्ट नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि नया एक्सप्रेस-वे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा। इससे परियोजना की भूमि अधिग्रहण लागत में 16 से 20 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही इसे आर्थिक औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा जिससे आसपास के इलाकों का विकास हो सके।

रिपोर्ट में लाजिस्टिक सेक्टर में बीमा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके बारे में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार लॉजिस्टिक बीमा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं है। बीमा कंपनियों को स्वयं ग्राहकों को आकर्षित करने वाले उत्पाद तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमा बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए।

Headline: Insurance Institute of India releases consolidated report
Publication: Navodaya Times
Edition: National
Ad Value: 1,03,545

इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जारी की संयुक्त रिपोर्ट

नई दिल्ली। बहुआयामी एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, टीसीआई ने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक खोजी अध्ययन जारी किया है, जिसमें भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बीमा की आवश्यकता का पता लगाया गया है। नई दिल्ली में परिवहन भवन में 17 अप्रैल, को आयोजित एक समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन मंत्री, नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री एंड बेयर फैक्ट्स नामक रिपोर्ट पेश की।

संयुक्त खोजी अध्ययन में पाया गया कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स अक्सर उच्च स्तरीय जोखिम में दबे होते हैं, जिसकी वजह उन पर और शिपर्स पर अनुचित तरीके से जोखिम ज्यादा लाद दिया जाता है। अक्सर अपनी गलती होने के बाद भी शिपर्स अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं लेकिन लागत उठानी पड़ती है एलएसपी को। इसे ध्यान में रखते हुए, अध्ययन ने सिफारिश की कि एलएसपी सरकार को अपील करें कि वह कार्गो मालिक की ओर से मालभाड़े में माल का बीमा अनिवार्य करवाए। यह भी सुझाव दिया गया कि सेक्टर को इंटरनल कैपेसिटी विकसित करने की आवश्यकता है जो बीमा आवश्यकताओं को समझे, जोखिम लेने की क्षमता का मूल्यांकन करें और भविष्य में बीमा खरीद के संबंध में ठीक और सामिल फैसले लिए जा सकें। टीसीआई ग्रुप के एमडी, विनीत अग्रवाल ने कहा, भारत में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कुछ अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

Headline: Land Acquisition cost to be low
Publication: Aaj Samaj
Edition: Bhopal, Indore , Gwalior
Ad Value: 93,288

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी, कहा

कम होगी भूमि अधिग्रहण की लागत

- पिछड़े व अविकसित इलाकों से होकर गुजरेगा राजमार्ग, दूरी भी होगी 125 किमी. कम
- इस एक्सप्रेस-वे को बनाने में आएगी करीब एक लाख करोड़ रुपए की लागत

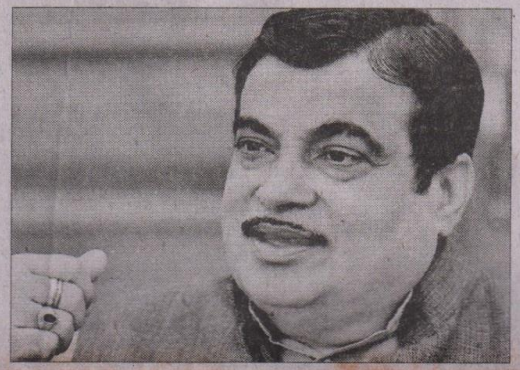

जयपुर से होकर गुजरेगा नया रूट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नया रूट दिल्ली की रिंग रोड से जयपुर, जयपुर से सवाई माधोपुर व वहां से वडोदरा होते हुए मुंबई पहुंचेगा। गडकरी ने ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में कहा कि नए एक्सप्रेस-वे राजमार्ग से इन दोनों महानगरों के बीच यात्रा दूरी 125 किलोमीटर कम होगी और कार से यह दूरी 11 घंटे में तय की जा सकेगी।

इन राज्यों में होगा विकास: उन्होंने कहा कि वडोदरा से मुंबई के बीच के हिस्से को 44,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसके लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। काम महीने भर में शुरू होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि नए एक्सप्रेस राजमार्ग से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के सामाजिक रूप से पिछड़े इलाकों के विकास की राह खुलेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली-मुंबई के बीच प्रस्तावित राजमार्ग के नए रूट से परियोजना की जमीन अधिग्रहण लागत 20,000 करोड़ रुपए तक कम होगी। इसके तहत यह राजमार्ग पिछड़े व अविकसित इलाकों से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही प्रस्तावित परियोजना से इन दो महानगरों के बीच यात्रा दूरी भी 125 किलोमीटर कम होगी। मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली व मुंबई के बीच मौजूदा राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण लागत सात करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर है। नई मार्ग रेखा में यह लागत घटकर 70 से 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर रह जाएगी। सरकार की दिल्ली व मुंबई को जोड़ने वाला एक नया एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक नए रूट से बनाने की योजना है। इसकी लागत एक लाख करोड़ रुपए आएगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि नए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण लागत 16,000 से 20,000 करोड़ रुपए कम रहेगी।

Headline: Expressway work to start in a month
Publication: Naya India
Edition: National
Ad Value: 79,742.25

एक माह में शुरू होगा एक्सप्रेस-वे का काम

नई दिल्ली ■ वार्ता

दिल्ली और मुंबई के बीच बनने वाले नये एक्सप्रेस-वे का काम एक महीने में शुरू हो जायेगा जिससे राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच की दूरी तकरीबन 135 किलोमीटर कम हो जायेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में बताया कि नये एक्सप्रेस-वे पर बड़ौदा-मुंबई खंड के पाँच में से चार पैकेज के लिए ठेके आवंटित किये जा चुके हैं। पाँचवें पैकेज का ठेका एक महीने में आवंटित हो जायेगा। इसके बाद इस खंड पर निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली-बड़ौदा खंड पर भी इसी साल काम शुरू होने की उम्मीद है। श्री गडकरी ने भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) और भारतीय परिवहन निगम (टीसीआई) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एक रिपोर्ट की लांचिंग के मौके पर कहा कि दिल्ली-मुंबई के मौजूदा सड़क मार्ग से एक्सप्रेस-वे का रास्ता अलग और छोटा होगा। नया एक्सप्रेस बनने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी करीब 135 किलोमीटर कम हो जायेगी और सफर घटकर 11 घंटे का रह जायेगा। इस प्रकार समय में 40 प्रतिशत की बचत होगी। इस पूरे एक्सप्रेस-वे पर कोई चेकपोस्ट नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि नया एक्सप्रेस-वे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा। इससे परियोजना की भूमि अधिग्रहण लागत में 16 से 20 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। साथ ही इसे आर्थिक औद्योगिक गलियारा बनाया जायेगा जिससे आसपास के इलाकों का विकास हो सके।

Headline: Nitin Gadkari emphasises upon need for reduction in logistic costs to increase exports
Publication: Focus News
Edition: Jaipur, Rajasthan
Ad Value: 76,670

Nitin Gadkari emphasises upon need for reduction in logistic costs to increase exports

New Delhi, Union Minister of Road Transport and Highways, Shipping, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Shri Nitin Gadkari has said that reduction in logistics cost can substantially increase the country's exports. He said, the government is concentrating on road improvement, reducing traffic density and introduction of alternative sources of fuels for the transport sector. All highways with over ten thousand PCU road density are being upgraded to four lanes, those with over twenty thousand PCU traffic units to six lanes and those with over thirty thousand PCU to eight lanes. Launching the joint study report on Insurance Requirements of the Indian Logistics and Warehousing Industry and their Customers in New Delhi today, the Minister informed that his Ministry has understood the need for bioethanol to fully cater to the gasoline blending demands of the nation. There is a potential for producing around 30 billion litres of ethanol annually from surplus agro-residues in the country. He also highlighted the importance of logistics and collection models suited for the country. The research study has been conducted by Transport Corporation of India and the Insurance Institute of India. It aims at providing an academic base for the Logistics and Warehousing Industry to educate their customers on utilising the full potential of insurance mechanism. It is understood that the report will help the logistics industry to protect their business interests in a better way.

Headline: Report on insurance requirements of logistics and warehousing released
Publication: Veer Arjun
Edition: National
Ad Value: 66,230.5

लॉजिस्टिक -वेयरहाउसिंग सेक्टर की बीमा जरूरतों पर संयुक्त रिपोर्ट जारी

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। भारत के अग्रणी बहुआयामी एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, टीसीआई ने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (आईआईआई) के साथ मिलकर एक खोजी अध्ययन जारी किया है, जिसमें भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बीमा की आवश्यकता का पता लगाया गया है। नई दिल्ली में परिवहन भवन में 17 अप्रैल, 2018 को आयोजित एक समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री एंड देयर कस्टमर्स नामक रिपोर्ट पेश की।

संयुक्त खोजी अध्ययन में पाया गया कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स (एलएसपी) अक्सर उच्च स्तरीय जोखिम में दबे होते हैं, जिसकी वजह उन पर और शिपर्स पर अनुचित तरीके से जोखिम ज्यादा लाद दिया जाता है। अक्सर अपनी गलती होने के बाद भी

सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री एंड देयर कस्टमर्स नामक रिपोर्ट जारी करते हुए।

शिपर्स अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं लेकिन लागत उठानी पड़ती है एलएसपी को। इसे ध्यान में रखते हुए, अध्ययन ने सिफारिश की कि एलएसपी सरकार को अपील करें कि वह कार्गो मालिक की ओर से मालभाड़े में माल का बीमा अनिवार्य करवाए। यह भी सुझाव दिया गया कि सेक्टर को इंटरनल कैपेसिटी विकसित करने की आवश्यकता है जो बीमा आवश्यकताओं को समझे, जोखिम लेने की क्षमता का मूल्यांकन करें और भविष्य में बीमा खरीद के संबंध में वैध और वाजिब फैसले लिए जा सके। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, टीसीआई ग्रुप के एमडी, विनीत अग्रवाल ने कहा, ठभारत में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कुछ अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, परिवहन किया जा रहा सभी सामान बीमित नहीं होता। वास्तव में, एलएसपी और वेअरहाउस सर्विस प्रोवाइडर्स (डब्लूएसपी) और ट्रांसपोर्टर अपने कस्टमर्स की ओर से 'डायरेक्ट कैश डेबिट्स' के लिए बीमा लेते हैं। यह एक बड़ी लागत है और इसके जोखिम का प्रभाव केवल बड़े संगठित ट्रांसपोर्टरों पर नहीं बल्कि छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिओ यह एक असहनीय जोखिम बन जाता है। इस अध्ययन को टीसीआई और आईआईआई द्वारा शुरू किया गया था ताकि विभिन्न मुद्दों और कारकों पर प्रकाश डाला जा सके ।

Headline: Target set for contractual arrangements of road and transport ministry
Publication: Dainik Sach Kahoun
Edition: Jaipur, Rajasthan
Ad value: 45,880

सड़क मंत्रालय के लिए ठेके देने का लक्ष्य तय

हमारा लक्ष्य राजमार्गों के नेटवर्क को बेहतर बनाना : गड़करी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 20,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के लिए विभिन्न कार्यों के ठेके देने का लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ठेके पर दिए गए 17055 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दिए गए कार्यों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 8652 किलोमीटर के लिए ठेके मंत्रालय द्वारा, 7397 किलोमीटर के लिए ठेके एनएचएआई द्वारा और 1006 किलोमीटर के लिए ठेके एनएचआईडीसीएल द्वारा दिए गए।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 16,420 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से

9700 किलोमीटर का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, 6000 किलोमीटर का निर्माण एनएचएआई द्वारा और 720 किलोमीटर का निर्माण एनएचआईडीसीएल द्वारा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 9829 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया था। चालू वर्ष के लिए प्रतिदिन 45 किलोमीटर का निर्माण लक्ष्य तय किया गया है, जबकि पिछले वर्ष निर्माण लक्ष्य प्रतिदिन लगभग 27 किलोमीटर का था।

गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश में राजमार्गों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के साथ-साथ इसे सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस वर्ष और ज्यादा निर्माण करने पर फोकस रहेगा, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा कार्यों के लिए ठेके दिए जाएंगे। इसी तरह सैद्धांतिक रूप से घोषित समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। गडकरी ने आज अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की जिसमें परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वार्षिक लक्ष्यों को तिमाही लक्ष्यों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए, ताकि वर्ष के आखिर में कोई दबाव न रहे। एनएचएआई के चेयरमैन ने वर्तमान में जारी परियोजनाएं पूरी करने के लिए अपने अधीन एक निगरानी समूह गठित किया है। मंत्रालय में इसी तरह का एक समूह गठित किया जा रहा है।

Headline: Nitin Gadkari launches Transport Corporation of India's report on Insurance requirements for Logistics and warehousing
Publication: Shah Times
Edition: National
Ad Value: 36,000

नई दिल्ली में परिवहन भवन में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन व राजमार्ग, नौवहन व जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री एंड देयर कस्टमर्स नामक रिपोर्ट पेश करते हुए।

THANK YOU

Transport Corporation of India Limited

TCI House, 69 Industrial Area
Sector-32, Gurugram-122 001
Tel: +91-124-2381603-07 **|** Fax: +91-124-2381611

Website: www.tcil.com | **E-mail:** corporate@tcil.com

CIN: L70109TG1995PLC019116